

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 18 अगस्त 2025 सोमवार

सम्पादकीय

वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग

यह अजीब संयोग है कि जिस दिन से राहुल गांधी, तेजस्वी सहित अनेक विपक्षी दलों ने बिहार से वोट रक्षा अभियान शुरू करने के साथ ही चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाये, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस वार्त कर अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया। शुद्ध मतदाता सूची समय की मांग है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग अनगिनत सवाल को बीच इस पर कितना खरा उतर पायोग।

वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विषय के आरोपों पर जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक भारत के सभी नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोटर बनाया चाहिए और वोट भी डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के ही होता है। ऐसे में चुनाव आयोग किसी दल के प्रति गलत भावना कैसे रख सकता है। उन्होंने कहा कि दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के निराधार आरोपों से तो निर्वाचन आयोग और न ही मतदाता भयभीत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लगे, क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' हो सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस राजनीतिक दल से संबंध रखता है। आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। चुनाव प्राधिकरण के समक्ष सत्तारूढ़ और विपक्षी दल समान हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से है। निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी का आरोप संविधान का अपमान है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा। इसमें अभी 15 दिन शेष हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि सभी हिताधारक पारदर्शी तरीके से एसआईआर को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही कहा था कि मशीन से पड़ी जा सकने वाली मतदाता सूची साझा करने से मतदाताओं की निजता भंग हो सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, उनके सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलए के सचिवायित दस्तावेज और टेक्स्टमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सभी हिताधारक मिलकर काम करके बिहार के एसआईआर को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एक बार जब एससीएलए द्वारा अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है, तो मसौदा सूची राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाती है। अंतिम सूची भी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है, यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है। मतदान केंद्रवार सूची दी जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक पोलिंग एजेंट नामित करने का अधिकार है और यही सूची पोलिंग एजेंट के पास भी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद भी, एक प्राक्धान है कि आप 45 दिनों के भीतर चुनाव न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। जब 45 दिन पूरे हो जाते हैं चाहे वह केवल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, और जब किसी भी पार्टी को 45 दिनों में कोई गलती नहीं मिली, तो आज इतने दिनों के बाद, इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे इनका मकसद क्या है, यह पूरे देश के लोग समझते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष इस प्रेस वार्ता को किस रूप में लेता है।

—प्रमोद भार्गव—

भगवान मोले नाथ का गुस्सा, प्रतीक रूप में मौत के तांडव नृत्य में फूटता है। देवमूर्ती उत्तराखंड में शिव के इस तांडव नृत्य का सिलसिला केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अभी भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की खीर गंगा नदी और धराली में बादल फटने और हर्षिल के तेल गाड़ नाले में बाढ़ आने से बड़ी तबाही हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हमें इसी गुस्से के प्रतीक रूप में देखने की जरूरत है। धराली में तो 50 से ज्यादा घर, 30 होटल और 30 होमस्टे मलबे में बदल गए। जो खीर नदी 10 मी. चौड़ी थी, वह जल प्रवाह से 39 मी. चौड़ी हो गई। अतएव जो भी सामने पड़ा उसे लीलाटी चली गई। प्रशासन वार लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के लापता होना बता रहा है। लेकिन हिमालय के बीचोबीच बसा खूबसूरत धराली गांव में संलाव गीचे उत्तरी हुए दिखा, उससे लगता है, मौत कहीं अधिक हुई है। प्रलय इतनी तीव्रता से आया की उसकी कान के पड़ फाड़ देने वाली गर्जना सुनने के बाद लोगों को बचने का समय ही नहीं मिल पाया। अब धराली मलबे में दमक है।

इस श्रृंखले के गर्म में समाई प्राकृतिक संघर्ष के दोहन से उत्तराखंड विकास की अग्रिम पांव में आ खड़ा हुआ था, वह विकास भीतर से कितना खूबसाला था, यह इस क्षेत्र में निरंतर आ रही इस आपदाओं से पता चलता है। बरिबर, बाढ़, भूस्खलन, बर्फ की चट्टानों का टूटना बर्फों का फटना, अनायास या संयोग नहीं है, बल्कि विकास के बहने पर्यावरण विनाश की जो पुरवृद्धि रही, उरसका परिणाम है। तबाही के इस कहर से यह भी साफ हो गया है कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारा न तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा से निपटने में



सक्षम है और न ही मौसम विभाग आपदा की सटीक भविष्यवाणी करने में समर्थ हो पाया है। यह विभाग केवल और बंगाल की खाड़ी के मौसम का अनुमान लगाने का दावा तो करता है, किन्तु मास्त के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हिमालय में बादल फटने की भी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। जबकि धराली क्षेत्र में एक साथ दो जगह बादल फट और कुछ मिनों में हुई तेज बारिश ने शीर्षखंड पर्यटन से निकली खीरगंगा नदी को प्रलय में बदलकर 90 प्रतिशत गांव को हिमालय के गर्म में समा दिया।

बादल फटना अनायास जरूर है, लेकिन ये करीब 10 किमी व्यास की परिक्षि में फटने के बाद अतिवृष्टि का कारण बनते हैं। 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश को बादल फटने की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बादल फटने की घटना के दौरान किसी एक स्थान पर एक घंटे के भीतर, उस क्षेत्र में होने वाली औसत, वार्षिक वर्षा की

अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार अटूट प्राकृतिक संघर्ष और खेती ही हैं। लेकिन उत्तराखंड हो या प्राकृतिक संघर्ष से भरपूर अन्य प्रदेश उद्योगपतियों की लॉबी जीडीपी और बिजली के कारण नगरीय विकास का अनुमान नहीं लगा पाते। इस कारण बादल फटने की घटनाओं की भविष्यवाणी भी नहीं करती हैं। समुद्रि, उन्मत्ती और वैज्ञानिक उपलब्धियों का चरम घुसने के बावजूद प्रकृति का प्रकोप घरा के किस हिस्से के तट से फूट पड़ेगा या आसमान से टूट पड़ेगा, यह जानने में हम बौने ही हैं। भूकंप की तो भनक भी नहीं लगती। जाहिर है, इसे रोकने का एक ही उपाय है कि विकास की जटिलवाजी में पर्यावरण की अनदेखी न करे। लेकिन विडंबना है कि घरेलू विकास दर को बढ़ावा देने के महीनजर आवासरचना विकास के बहाने देशी-विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षी स्वीकृतिपूर्ण राज्य सरकारें नहीं नादियों का उद्गम स्थल है। इन नादियों के उद्गम स्थलों और किनारों

पर पुराणों में दर्ज अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल हैं। इसलिए इसे 6 र्म-ग्रंथों में देवभूमि कहा गया है। यहां के पनाच्छदित पहाड़ अटूटी जो विविधता के पर्याय हैं। तथ्य है, उत्तराखंड प्राकृतिक संघर्षों का खजाना है। इसी वेशकीमती भंडार को सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की नजर लग गई है, जिसकी वजह से प्रलय जैसे प्रकोप बार-बार इस देवभूमि में बर्बादी की आपदा वर्षा रहे हैं।

उत्तराखंड की तबाही की इबारत हिमाली में गंगा नदी पर बने बाढ़ बां के निर्माण के साथ ही लिख दी गई थी। नदीजलन बड़ी संख्या में लोगों का पुस्तनी ग्राम-कस्बों से विस्थापन तो हुआ ही, लाखों हेक्टेयर जंगल भी तबाह हो गए। बांध के निर्माण में विस्फोटकों के इस्तेमाल ने धरती के अंदरूनी पारिस्थिकी तंत्र के ताने-बाने को खंडित कर दिया। विद्युत परियोजनाओं और सड़कों का जाल विमान के लिए भी घमाकों का अनवरत सिलसिला जारी रहा। अब यही काम रेल पथ के लिए सुरुंग बनाने में सामने आ रहा है। विस्फोट से फैले मलबे को भी नदियों और हिमालयी झीलों में डहा दिया जाता है। नदीजलन नदियों का तल मलबे से भर गए हैं। दुर्घपरिणाम स्वरूप इनकी जलधारण क्षमता नष्ट हुई और जल प्रवाह बाधित हुआ। अतएव जब भी तेज बारिश आती है तो तुरंत बाढ़ में बदलकर विनाशालीला में तब्दील हो जाती है। बादल फटने के तो केदारनाथ और अब धराली जैसे परितम निकलते हैं। उत्तरकाशी जेशीमठ में तो निरंतर बाढ़ और भू-स्खलन देखने में आ रहे हैं, इस क्षेत्र के संकटों मकानों में भूमि घसकने से बड़ी-बड़ी दरारे आ गई हैं। भू-स्खलन के अलावा इन दरारों की वजह कांश्चिदी और असिगंगा नदियों पर निर्माणवादी विध्वंसित और रेल परियोजनाएं भी रही हैं। उत्तराखंड जब स्वतंत्र राज्य नहीं बना था, तब इस देवभूमि क्षेत्र में पड़

“चिप वॉर” के क्षेत्र में भारत

—नीरज कुमार दूबे—

अमेरिका और चीन के बीच चल रही “चिप वॉर” अब सिर्फ दो महाशक्तियों का द्वंद नहीं रही, बल्कि वैश्विक तकनीकी शक्ति संतुलन का केंद्रीय मुद्दा बन चुकी है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका, एशियाईया और एमपीडी जैसी कंपनियों के चीन को बेचे जाने वाले आईडि चिप की बिक्री से 15: हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर रहा है। यह कदम बताता है कि अब सरकारें भी सीधे हार्ड-वेयर कारोबार में “स्टेकहोल्डर” बनने लगी हैं। इसके पीछे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ रणनीतिक भू-राजनीतिक समीकरण भी छिपे हैं। मसलन दुग्ध प्रशासन की विधि चिप की पारबंदी, चीन का दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और फिर टैरिफ युद्ध में अस्थायी विराम। हम आगे याद दिला दें कि दुग्ध प्रशासन ने अप्रैल में बीजिंग के साथ व्यापारिक टकराव के चलते चीन को चिप की बिक्री पर रोक लगाई थी। लेकिन चीन द्वारा अमेरिका को दुर्लभ वायुओं (लिंग तन्त्रों) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुग्ध को यह पारबंदी हटानी पड़ी थी।

इस पूरी घटना से एक बड़ा संकेत यह निकलता है कि तकनीकी क्षेत्र की खींचतान अब स्थायी हो चुकी है। चाहे वह अमेरिका द्वारा चीन को चिप बेचना हो या चीन का भारत की तकनीकी विनिर्माण क्षमता को कमजोर करने की कोशिश (जैसे हाल में फॉक्सकॉन के भारत स्थित संज में चीनी इंजीनियरों की वापसी), यह एक ऐसा रणनीतिक क्षेत्र है जिसे हर देश अपने हितों में इस्तेमाल या हथियार बनाने की कोशिश करेगा।

इस शक्ति-संघर्ष में भारत की स्थिति पर गौर करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जहां चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर श्रेष्ठता के कारण अमेरिकी टैरिफ से बच निकलते हैं, वहीं भारत को दुग्ध जैसे निर्यातों की जरूरत में अब भी एक उष्णनीतिक क्षेत्र का वैश्विक तकनीकी ट्रेडल पर निर्णायक सीट चाहिए, तो उसे सेमीकंडक्टर और आईआई में ठोस



बढ़त लेनी होगी।

प्रधानमंत्री नोदी इस बात को बहुत पहले से समझ रहे थे इसलिए उनकी सरकार ने दिसंबर 2021 में शुरू किए गए भारत सेमीकंडक्टर मिशन को अब एक आक्रामक औद्योगिक अभियान में बदल दिया है। 10 अरब डॉलर से अधिक का प्रोत्साहन पैकेज और राज्यों में फैले सेमीकंडक्टर पार्क इस दिशा में पहला कदम थे। ताजा फैंसले के तहत, प्रशासनी नरेश मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें ओडिशा में सिकसम की देश की पहली वाणिज्यिक कम्पाउंड फ्रैक्शनेशन इकाई, 3डी ग्लास संयंत्र की उन्नत पैकेजिंग इकाई, आंध्र प्रदेश में एसआईआई की मेन्यूफैक्चरिंग यूनिट और पंजाब में सीडीआईएल का विस्तार शामिल हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 4,600 करोड़ रुपये का निवेश होना और 2,000 से अधिक कुशल पेशेवरों को प्रस्थारण प्रमोशन मिलेगा, साथ ही उनके अत्यल्प अससर भी सुनिश्चित होंगे।

इससे भारत को सिलिकॉन काबांड आधुनिक कम्पाउंड चिप, अत्युत्पादक पैकेजिंग तकनीक और उच्च-प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन में तेजी क्षमता मिलेगी, जो अब तक ताइवान, दक्षिण कोरिया या चीन के पास ही केंद्रित थी।

कहा जाये तो दुनिया का तकनीकी परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप, चीन-निर्मित आधुनिक युद्धास्त्र से बाहर निकलना चाहते हैं। भारत एक सिलिकॉन लोकतंत्र, विशाल बाजार और कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा के चलते स्वाभाविक विकल्प है। हमारी लागत-प्रतिस्पर्धा और डिजाइन

शहर, कुत्ते और हमारी जिम्मेदारी



—डॉ प्रियंका सोरभ—

भारत में पालतू कुत्तों की संख्या 2023 में लगभग 3.2 करोड़ आंकी गई, और यह हर साल 12-15% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन शहरों में कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका कारण है कि लोग कुत्तों को पालतू कुत्तों के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में वे अक्सर अनाथ कुत्ते हैं। इन कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो नगरपालिकाओं को चुनौती दे रहा है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।



तो वह तुलसी पालीबिना बेग निकालकर उसे उछालता है। और नजदीकी उरुद्विन में डालता है। इसके लिए कई नगरपालिकाएं मुक्त वेत और पौटी इस्टेबल उपलब्ध कराती हैं। इसका कारण है कि लोग कुत्तों को पालतू कुत्तों के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में वे अक्सर अनाथ कुत्ते हैं। इन कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो नगरपालिकाओं को चुनौती दे रहा है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

पालतू कुत्ते का प्रशिक्षण कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः एक अनाथ कुत्ता है और उसका व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से विकसित देशों में नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

पालतू कुत्ते की पौटी में कई प्रकार के बैक्टीरिया, परजीवी और रोगजनक तत्व हो सकते हैं। ये रोगाणु हैं जो पालतू कुत्तों की पौटी से फैल सकते हैं। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को इन कुत्तों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

में प्राप्त 229 इवेंट का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। कॉलर संतुष्टि का प्रतिशत 89.47 रहा।

फाँसी खानेवाला रात को फाँसीलाने
फाँसीलाने फाँसीलाने जमाने दे दी। सुनना
पर पहुँची सुनने में शिव को कब्र में
मिले। घटना को घोरामादम के तिरि ने कब्र में
है। घटना से गाँव में सन्माना परतना
हुआ है। कपरिजान का कहना है कि
गाँव में देदी को जमाने दे दी। सुनना
का कहना है जमाने से जमाना था। इसने
नायका हाकर देदी को कब्र में (16)पुत्री
रामानने ने खुदकुशी कर दी। मुनका
की माँ मीरा भी रामानने ने मुनिस
को रिशत परतने में बताया कि जमाना
कब्र को उतकी देदी की रिशत उजामनी
महासव देखने जमाने की जिद
रही थी। देर साता कायदाम में जमाने
से माँ ने परे मना कर दिया तो इसने
नायका हाकर रिशत अपने कब्र में
देदी रही। रात लगाम देर बजे जमाने
देदी को जमाने दे दी। जमाने से बने
कब्र में पहुँची तो जमाने का दृश्य
देखकर उल्टे होरा उड़ पड़ा। रिशत
दुपुष्ट के लहरी हुई थी। फाँसी से लगे
पुष्ट पर लहरी हुई थी। कपडों से लगे
पुष्ट को भी गीने उतारा और
चापने पर लिटाया जमाने देर तक
उतकी मीरा ही चुकी थी। घटना की
सुनना थापर दे दी। सुनना पाकर
थामाकस नायका जमाना श्रीवास्तव
भीतर पर पहुँचे। उतनेही रात को कब्रों
में लेकर घोरामादम के लिपि में
थामाकस। थामाकस ने बताया कि मुनका
की माँ ने कालावस्था से संकीर्तिना कायद
रही है। हालांकि फाँसी का कारण
सुनने नहीं हो पाया है। पुनिस को
पसतुआ से पर जमाने रही हैं।
घोरामादम रिपोर्त आने के बाद भी
लिपि साता हो सकेगी। गाँव में
जमाना का कहना है कि रिशत पावले
में अच्छी थी उतपर से हाता रहती
थी। अजनाक रजामा देर तक कदम
से परिशर और गाँव से पर में कोहराम
नहीं है। घटना के बाद से पर में कोहराम
नया हुआ है।

दैनिंक

भारतीया बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व.
रविचंद्र चन्द्र पाण्डेय
प्रस्ताविका रिशत, प्रकाशक, मुद्रक
प्रतिष्ठान चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रकाशित
प्रतिष्ठान प्रेम प्रतिष्ठान, नया हाल
1-14 लोहना कापमलेनस
जिला पंजाथ जमाने कपरिजान
बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं
प्रकाशित।

प्रबंध सम्पादक-दिनेश सिंह
संस्थापक सम्पादक-दीपक चन्द्र पाण्डेय
अधोया-फैनाबर कायलाने
जमाने मंदिर परिसर लखनवा
अधोया-फैनाबर कायलाने
लखनवा कायलाने
तारकाने फाँसीलाने, एल.एड.ए. कोलोन
गोखर पुर, कानपुर उर लखनवा
संस्थापक कायलाने
लखनवा कायलाने
नौ. 9336715406, 8400925463
Email: dhanu.bharti@rediffmail.com
dhanu.bharti@rediffmail.com